

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 01-01-2026

- » पीएम द्वारा प्रगति(PRAGATI) की 50वीं बैठक की अध्यक्षता
- » RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
- » भारत में किसानों की आत्महत्याएँ: 28 वर्ष का डेटा
- » कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ भारत का रूपांतरण(Transforming India with AI)

### संक्षिप्त समाचार

- » महिला की आय क्षमता पिता को अभिभावकीय जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करती: उच्च न्यायालय
- » हिमाचल प्रदेश विनियमित भांग की खेती की राह पर
- » हनिमाद्दू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
- » महाराष्ट्र में प्रमुख छह-लेन ग्रीन कॉरिडोर को स्वीकृति
- » DRDO द्वारा दो प्रलय मिसाइलों का साल्वो लॉन्च
- » राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन रूपरेखा (NTRAF)
- » अमेज़न के डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार
- » कीटों में माइटोकॉन्फ्रिया का विकास
- » राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA)
- » ग्राम रक्षा गार्ड (VDG)

## पीएम द्वारा प्रगति(PRAGATI) की 50वीं बैठक की अध्यक्षता

### संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की।

### परिचय

- PRAGATI** (सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन) एक प्रौद्योगिकी-संचालित शासन और निगरानी मंच है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने 2015 में शुरू किया।
- उद्देश्य:** लोक प्रशासन में सुधार करना और सरकारी कार्यक्रमों व परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना।
- प्रगति एक त्रिस्तरीय मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें तीन पदानुक्रम स्तर शामिल हैं: शीर्ष पर प्रधानमंत्री कार्यालय, मध्य स्तर पर केंद्रीय सरकार के सचिव, और आधार स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव।
- प्रगति की प्रमुख विशेषताएँ:**

Monitors and reviews key programmes and projects by the Government of India.

Addresses issues flagged by State Governments, ensuring their concerns are heard.

Enhances transparency and improves accountability in project implementation.

Built-in feature to maintain decisions for follow-up and continuous review.

Facilitates real-time collaboration and exchange among various stakeholders.

Enables the PMO's office to resolve implementation issues and expedite project completion.

Tackles bottlenecks in projects caused by interdependencies across government bodies.

Operates with a three-tier IT-based system involving the PMO, GoI Secretaries, and State Chief Secretaries.

- प्रगति के मुख्य उद्देश्य हैं:

- परियोजना निगरानी:** उच्च-मूल्य और महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखना तथा विलंब या अवरोधों को दूर करना।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन:** सरकारी योजनाओं और मिशनों का समयबद्ध एवं कुशल निष्पादन सुनिश्चित करना।

- शिकायत निवारण:** नागरिक शिकायतों के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) जैसे तंत्रों के साथ एकीकृत होकर लगातार सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना।

### मुख्य उपलब्धियाँ

- प्रगति के अंतर्गत 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, और इन परियोजनाओं में पहचानी गई 3,162 समस्याओं में से 2,958 अर्थात् लगभग 94% का समाधान किया गया है।
- कई परियोजनाएँ जो दशकों से रुकी हुई थीं, प्रगति मंच पर लिए जाने के बाद पूरी हुई या निर्णायक रूप से आगे बढ़ाई गईं।

### निष्कर्ष

- प्रगति एक संस्थागत नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत के विकासात्मक शासन की मूलभूत चुनौतियों—परियोजना निष्पादन में विलंब, अंतर-सरकारी समन्वय की विफलताएँ, एवं जवाबदेही की कमी—को संबोधित करता है।
- यह मंच दर्शाता है कि कैसे रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग और उच्च-स्तरीय जवाबदेही मिलकर शासन की प्रभावशीलता को बदल सकते हैं।

### स्रोत: PIB

## RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

### संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दिसंबर 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) भारत के वित्तीय क्षेत्र के प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करती है और घरेलू तथा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बैंकों की लचीलापन का मूल्यांकन करती है।

### रिपोर्ट की प्रमुख बातें

- सकारात्मक विकास परिदृश्य:** RBI ने उल्लेख किया कि वास्तविक GDP वृद्धि FY 2025-26 की प्रथम दो तिमाहियों में अपेक्षा से अधिक रही, Q1 में 7.8% और Q2 में 8.2% दर्ज की गई।

- वृद्धि को सुदृढ़ निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश ने समर्थन दिया।
- बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की परिसंपत्ति गुणवत्ता और बेहतर हुई है। सितंबर 2025 में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात घटकर 2.1% हो गया।
  - सुदृढ़ वसूली, विवेकपूर्ण ऋण प्रथाएँ और बेहतर जोखिम प्रबंधन ने इस सुधार को समर्थन दिया।
- पर्याम पूंजी बफर:** सितंबर 2025 तक जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के अनुपात पर पूंजी (CRAR) सुदृढ़ रही, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 16% और निजी क्षेत्र के बैंकों में 18.1%।
- असुरक्षित ऋण बने प्रमुख जोखिम:** असुरक्षित ऋण कुल खुदरा ऋण डिफॉल्ट का 53.1% हिस्सा रहा। निजी बैंकों में असुरक्षित ऋणों का योगदान लगभग 76% रहा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह 15.9% था।
- फिनटेक ऋण:** RBI ने उन उधारकर्ताओं में उच्च हानि को चिन्हित किया जिन्होंने पाँच या अधिक ऋणदाताओं से असुरक्षित ऋण लिया है, जिससे फिनटेक कंपनियों की भूमिका उजागर हुई।
  - फिनटेक ऋण पोर्टफोलियो का 70% से अधिक हिस्सा असुरक्षित ऋणों से बना है।
- स्टेबलकॉइन से मौद्रिक संप्रभुता को जोखिम:** RBI ने पुनः चिंता व्यक्त की कि स्टेबलकॉइन केंद्रीय बैंकों की मुद्रा आपूर्ति और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करने की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं।
  - विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित स्टेबलकॉइन से मौद्रिक संप्रभुता का क्षरण हो सकता है और मौद्रिक नीति के प्रसारण को कमजोर कर सकता है।
- रुपये का अवमूल्यन:** रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन हुआ, जिसका कारण व्यापार शर्तों में गिरावट, उच्च शुल्क और पूंजी प्रवाह में मंदी रहा।

### वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक द्विवार्षिक प्रकाशन है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और लचीलापन का आकलन करता है।
- यह वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न घटकों जैसे बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFCs), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ और वित्तीय बाजारों के स्वास्थ्य पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

स्रोत: [TOI](#)

## भारत में किसानों की आत्महत्याएँ: 28 वर्ष का डेटा

### संदर्भ

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, 1995 से 2023 के बीच भारत में 3.9 लाख से अधिक किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की।
  - महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने मिलकर कुल आत्महत्याओं का 70% से अधिक हिस्सा दर्ज किया।

### परिचय

- निरंतर एक दशक की गिरावट के पश्चात, 2023 में किसान आत्महत्याओं में 2022 की तुलना में 75% की वृद्धि हुई, कुल 10,786 मृत्युएँ दर्ज की गईं।
  - इनमें से 6,096 कृषि मजदूर थे, जिन्होंने प्रथम बार कृषकों (4,690 मृत्युएँ) को पीछे छोड़ दिया।
- यह गहरे ग्रामीण संकट को रेखांकित करता है—मजदूर वेतन असुरक्षा, मौसमी बेरोजगारी, बढ़ती खाद्य कीमतें और सीमित सामाजिक सुरक्षा से जूझते हैं, जिससे वे आर्थिक आघातों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाते हैं।

### भारत में किसान आत्महत्याओं के मूल कारण

- ऋणग्रस्तता और ऋण संकट:** प्रत्येक वर्ष 11,000 से अधिक किसान आत्महत्याएँ बकाया ऋण से जुड़ी होती हैं, प्रायः निजी साहूकारों से लिए गए ऋण जिन पर 24–60% वार्षिक ब्याज लिया जाता है।

- उच्च इनपुट लागत, फसल विफलता और संस्थागत क्रण की कमी के कारण कई किसान क्रण के चक्र में फँस जाते हैं।
- छोटे किसानों के लिए संस्थागत क्रण अब भी अप्राप्य है।
- फसल विफलता और जलवायु संकट:** अनियमित मानसून, लंबे सूखे और कीट हमलों ने बार-बार फसल विफलता उत्पन्न की।
  - महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जलवायु-जनित उत्पादन गिरावट के हांटस्पॉट हैं।
- इनपुट लागत मुद्रास्फीति:** उर्वरक, बीज और डीजल की बढ़ती लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आगे निकल गई है।
  - किसान प्रति एकड़ ₹20,000–₹30,000 निवेश करते हैं लेकिन अक्सर आधे से भी कम वसूल पाते हैं।
- बाजार विकृति और मूल्य अस्थिरता:** सुनिश्चित खरीद की अनुपस्थिति, मध्यस्थों पर निर्भरता और नाशवान फसलों का बाजार अधिशेष कीमतों को उत्पादन लागत से नीचे धकेल देता है।
- संस्थागत विफलता और विलंबित मुआवज़ा:** मुआवज़ा योजनाएँ (PMFBY, किसान क्रेडिट कार्ड) प्रायः विलंब या कुप्रबंधन का शिकार होती हैं, जिससे कटाई के पश्चात हानि के समय निराशा बढ़ती है।
- सामाजिक-मानसिक कारक:** दीर्घकालिक क्रण, सामाजिक सुरक्षा की कमी और दिवालियापन से जुड़ा सांस्कृतिक कलंक किसानों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करता है।
- भूमि विखंडन और कम उत्पादकता:** 85% जोतें 2 हेक्टेयर से कम हैं, जिससे वे यंत्रीकरण या सिंचाई निवेश के लिए आर्थिक रूप से अनुपयुक्त हो जाती हैं।
- नीतिगत खामियाँ:** समर्थन योजनाओं का अपर्याप्त कार्यान्वयन, फसल बीमा की कम पहुँच और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपर्याप्त खरीद ने किसानों को असुरक्षित छोड़ दिया है।

- भारत का ग्रामीण संकट संरचनात्मक असमानता, नीतिगत उपेक्षा और बाजार असुरक्षा का परिणाम है, जो फसल विफलता या क्रण के साथ मिलकर दीर्घकालिक प्रणालीगत बदलाव की माँग करता है, न कि अस्थायी उपायों की।

### कृषि संकट का क्षेत्रीय संकेंद्रण

- दक्षिण और पश्चिम भारत में 1995 से दर्ज सभी किसान आत्महत्याओं का 72.5% हिस्सा है।
  - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने इस अवधि में 1,70,000 से अधिक आत्महत्याएँ दर्ज की हैं।
  - 2014 में तेलंगाना के गठन के पश्चात, नया राज्य शीघ्र ही उच्च-संकट क्षेत्र के रूप में उभरा, जिसने सबसे संवेदनशील कपास-उगाने वाले जिलों को विरासत में लिया।
- मध्य प्रदेश शीर्ष योगदानकर्ताओं में शामिल है, यह दर्शाता है कि कृषि संकट क्षेत्रीय सीमाओं से परे है।

### किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए प्रमुख सरकारी प्रयास

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):** वित्तीय संकट और अनौपचारिक क्रण पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य।
  - प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाली हानि को कवर करता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:** किसानों को सम्बिडी वाले ब्याज दरों पर अल्पकालिक क्रण प्रदान करता है।
  - उच्च-ब्याज वाले अनौपचारिक क्रणों पर निर्भरता कम करने में सहायता करता है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):** छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करता है।
  - आय को पूरक करने और बुनियादी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य।
- राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022):** भारत की प्रथम व्यापक आत्महत्या रोकथाम नीति, जिसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है।

- ▲ ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रमों को शामिल करता है जैसे:
    - **टेली-MANAS:** 24/7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन।
    - **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP):** सामुदायिक-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है।
    - **मनोदर्पण:** किशोर मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल-आधारित परामर्श पर केंद्रित।
  - ▲ **कानूनी और नीतिगत ढाँचे**
    - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** आत्महत्या को अपराधमुक्त करता है और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
    - **स्वास्थ्य नीति 2014:** मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक मान्यता देता है।
  - **राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप**
    - ▲ **महाराष्ट्र:** संकटग्रस्त किसानों के लिए विशेष पैकेज, क्रृषि माफी और परामर्श केंद्र।
    - ▲ **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना:** क्षेत्रीय कृषि संकट को संबोधित करने के लिए केंद्रित अध्ययन और नीतिगत सुधार।
- मनरेगा और राहत का दौर**
- 2010 से 2019 तक, कई राज्यों में किसान आत्महत्याएँ उल्लेखनीय रूप से कम हुईं।
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण रहा, जिसने सूखे और गैर-कृषि मौसमों के दौरान वेतन सुरक्षा प्रदान की।
  - अन्य उपाय जैसे विस्तारित फसल बीमा और क्रृषि राहत योजनाओं ने ग्रामीण आय को स्थिर करने में मदद की।
    - ▲ केरल में आत्महत्याएँ 2005 में 1,118 से घटकर 2014 में 105 हो गईं।
    - ▲ पश्चिम बंगाल ने 2012 तक शून्य आत्महत्याएँ दर्ज कीं।
- ▲ मध्य प्रदेश ने वर्षों के संकट के पश्चात लगातार कमी का अनुभव किया।
- आगे की राह**
- **संस्थागत क्रृषि पहुँच:** ग्रामीण बैंकिंग को सुदृढ़ करना और अनौपचारिक क्रृषिदाताओं पर निर्भरता कम करना।
  - **MSP के लिए कानूनी समर्थन:** सर्वोच्च न्यायालय पैनल की सिफारिश के अनुसार, MSP को कानूनी गारंटी देना किसानों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है।
  - **मानसिक स्वास्थ्य समर्थन:** ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और मानसिक बीमारी को कलंकित करने से रोकना।
  - **जलवायु-लचीली कृषि:** सतत प्रथाओं और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना ताकि जलवायु जोखिमों को कम किया जा सके।
- स्रोत:** DTE
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ भारत का रूपांतरण (Transforming India with AI)**
- समाचारों में**
- भारत एक एआई-संचालित युग में प्रवेश कर रहा है जहाँ प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा में सुधार, किसानों को समर्थन एवं शिक्षा को सशक्त बनाकर दैनिक जीवन को परिवर्तित कर रही है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?**
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मशीनों की वह क्षमता है जिससे वे ऐसे कार्य कर सकती हैं जो सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता रखते हैं।**
  - यह प्रणालियों को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाती है।
  - यह डेटासेट, एल्गोरिद्म और बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके जानकारी का विश्लेषण करती है, पैटर्न पहचानती है तथा उत्तर प्रस्तुत करती है।

- ▲ समय के साथ ये प्रणालियाँ अपने प्रदर्शन में सुधार करती हैं, जिससे वे तर्क कर सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और मनुष्यों के समान तरीकों से संवाद कर सकती हैं।

### अनुप्रयोग

- **दैनिक जीवन में एआई:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, शासन और जलवायु सेवाओं को तीव्र, स्मार्ट और अधिक सुलभ बना रही है।
- ▲ बड़े भाषा मॉडल चैटबॉट, अनुवाद उपकरण और वर्चुअल असिस्टेंट को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे लोग अपनी भाषाओं में जानकारी, सरकारी सेवाएं एवं शिक्षा तक पहुँच पाते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा:** रोगों की प्रारंभिक पहचान, चिकित्सीय छवि विश्लेषण और व्यक्तिगत उपचार सहायता।
- **एआई-सक्षम टेलीमेडिसिन ग्रामीण रोगियों को विशेषज्ञों से जोड़ता है।**
- **HealthAI में वैश्विक सहयोग और भागीदारी नैतिक और सुरक्षित एआई उपयोग को बढ़ावा देती है।**
- **कृषि:** एआई मौसम की भविष्यवाणी करता है, कीटों का पता लगाता है और सिंचाई व बुवाई पर परामर्श देता है।
  - ▲ किसान ई-मित्र, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली और फसल स्वास्थ्य निगरानी जैसी पहलें कृषि उत्पादकता एवं आय सुरक्षा में सुधार करती हैं।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** NEP 2020 के अंतर्गत कक्षा VI से एआई शिक्षा शुरू की गई।
  - ▲ DIKSHA प्लेटफॉर्म पहुँच के लिए एआई का उपयोग करता है, जिसमें पढ़कर सुनाने और खोज उपकरण शामिल हैं।
  - ▲ YUVAi कार्यक्रम छात्रों (कक्षा 8–12) को सामाजिक और विकासात्मक विषयों में एआई लागू करने में सक्षम बनाता है।
- **शासन और न्याय वितरण:** एआई अनुवाद, केस प्रबंधन, शेड्यूलिंग और नागरिक सेवाओं का समर्थन करता है, विशेषकर ई-कोर्ट्स परियोजना के अंतर्गत।

- ▲ निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और न्याय तक पहुँच में सुधार होता है।

- **मौसम पूर्वानुमान और जलवायु सेवाएँ:** एआई मॉडल वर्षा, चक्रवात, कोहरा, विद्युत और आग की भविष्यवाणी में सुधार करते हैं।
  - ▲ एडवांस्ड ड्वोराक तकनीक और आगामी मौसमजीपीटी जैसे उपकरण किसानों एवं आपदा प्रबंधन का समर्थन करते हैं।

### भारत में वर्तमान एआई पारिस्थितिकी तंत्र

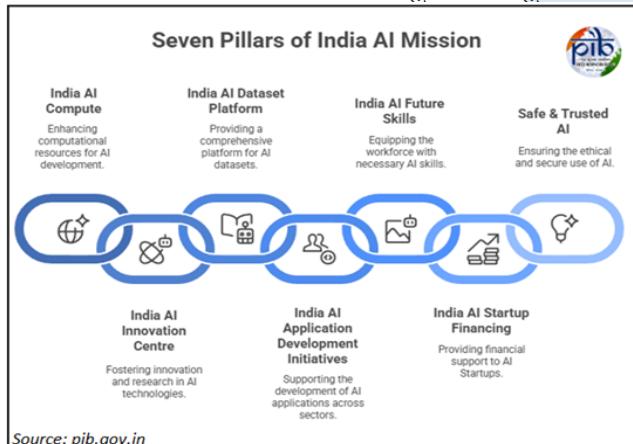
- भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तीव्रता से विस्तार कर रहा है, जिसकी वार्षिक आय इस वर्ष USD 280 बिलियन से अधिक होने की संभावना है।
- 6 मिलियन से अधिक लोग टेक और एआई पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यरत हैं।
- भारत में 1,800+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, जिनमें से 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं।
- भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप हैं, और विगत वर्ष शुरू किए गए लगभग 89% नए स्टार्टअप ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग किया।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अक्सर नौकरियों के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह नए अवसर सृजित कर रही है।
  - ▲ किसान ई-मित्र, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली और फसल स्वास्थ्य निगरानी जैसी पहलें कृषि उत्पादकता एवं आय सुरक्षा में सुधार करती हैं।
- **NASSCOM की रिपोर्ट ‘एडवांसिंग इंडिया’ज एआई स्किल्स** (अगस्त 2024) के अनुसार, भारत का एआई प्रतिभा आधार 6–6.5 लाख पेशेवरों से बढ़कर 2027 तक 12.5 लाख से अधिक होने की संभावना है, 15% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ।
- एआई अपनाने वाले प्रमुख क्षेत्र औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएँ एवं खुदरा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा, तथा स्वास्थ्य सेवा हैं।
  - ▲ ये मिलकर एआई के कुल मूल्य का लगभग 60% योगदान करते हैं।
  - ▲ BCG सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 26% भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर एआई परिपक्वता प्राप्त की है।

## वैश्विक रैंकिंग

- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धा में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत की तीव्रता से बढ़ती स्थिति को रेखांकित करती है।

## संबंधित कदम

- भारत एआई मिशन, मार्च 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के पाँच वर्षीय बजट के साथ स्वीकृत किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक नेता बनाना है, दृष्टि के तहत: “मेकिना एआई इन इंडिया एंड मेकिना एआई वर्क फॉर इंडिया”।
  - इसने एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना को काफी बढ़ाया है, GPU उपलब्धता को प्रारंभिक लक्ष्य 10,000 से बढ़ाकर 38,000 कर दिया है, जिससे उन्नत एआई संसाधनों तक सस्ती पहुँच संभव हुई है।



- कृत्रिम बुद्धिमत्ता 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 का प्रमुख केंद्र था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “इनॉवेट टू ट्रांसफॉर्म” थीम के अंतर्गत किया।
- भारत सरकार अपनी एआई दृष्टि को सक्रिय रूप से लागू कर रही है, जिसमें नीति, अवसंरचना, अनुसंधान और कौशल विकास को मिलाकर एक समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

- मुख्य प्रयासों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, सतत शहरों और शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, साथ ही भविष्य-तैयार कार्यबल तैयार करने के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं।
- एआई दक्षता ढाँचा सरकारी अधिकारियों को शासन में एआई लागू करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जबकि UIDAI के साथ सर्वम AI जैसी साइबरारियाँ सुरक्षित, संप्रभु एआई मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को सुदृढ़ कर रही हैं।
- भाषिणी जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देते हैं, सेवाओं तक बहुभाषी पहुँच सक्षम करते हैं, और भारतजेन AI भारत का प्रथम सरकारी-वित्त पोषित, स्वदेशी मल्टीमॉडल बड़ा भाषा मॉडल है जो 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।

## चिंताएँ और मुद्दे

- एआई-संचालित चेहरे की पहचान और पुलिसिंग नागरिक स्वतंत्रता चिंताओं को उत्पन्न करती है क्योंकि नियमन का अभाव है।
- आगामी पीढ़ी के एआई मॉडल साइबर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं यदि हैकिंग या धोखाधड़ी के लिए दुरुपयोग किया जाए।
- इंडिया एआई ने वह बाधाएँ बताई हैं जैसे वहनीयता, डेटा गुणवत्ता और अवसंरचना की कमी, जो एआई अपनाने को धीमा करती हैं।
- यदि सावधानीपूर्वक निगरानी न की जाए तो एआई प्रणालियाँ क्रेडिट स्कोरिंग, भर्ती और शासन में पक्षपात को बनाए रखने का जोखिम रखती हैं।

## निष्कर्ष और आगे की राह

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्याय और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत के विकास को तीव्र करने की अपार क्षमता प्रदान करती है, लेकिन अनियमित उपयोग गोपनीयता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही को खतरे में डाल सकता है।
- इसके लाभों का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए भारत को नवाचार और सुदृढ़ नैतिक ढाँचे के बीच संतुलन बनाना होगा, नौकरी विस्थापन को संबोधित

करने के लिए कौशल एवं समावेशन में निवेश करना होगा, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक साझेदारियाँ बनानी होंगी, तथा एआई तैनाती में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

- भारत एआई मिशन और आधारभूत मॉडल विकास जैसी प्रमुख पहलें सुनिश्चित करती हैं कि एआई प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुँचाए, कौशल और अनुसंधान को सुदृढ़ करे, और भारत को “विकसित भारत 2047” की दृष्टि के अनुरूप एक वैश्विक एआई नेता के रूप में स्थापित करे।

स्रोत : [PIB](#)

## संक्षिप्त समाचार

**महिला की आय क्षमता पिता को अभिभावकीय जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करती: उच्च न्यायालय**

### संदर्भ

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि बाल भरण-पोषण साझा अभिभावकीय जिम्मेदारी और बच्चे के समर्थित होने के अधिकार की मान्यता है।
  - इसने यह भी कहा कि यह न तो कोई उपकार है और न ही गैर-अभिभक्षक अभिभावक के विरुद्ध दंडात्मक उपाय।

### परिचय

- एक याचिका पर निर्णय लेते हुए न्यायालय ने नोट किया कि बच्चे की दैनिक आवश्यकताएँ कानूनी याचिकाओं में सटीक रूप से परिभाषित की जा सकने वाली सीमाओं से कहीं अधिक होती हैं।
  - इनमें स्कूल से संबंधित आवश्यकताएँ, छोटे चिकित्सीय व्यय, शौक, सामाजिक संपर्क और सामान्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं।
- न्यायालय ने यह भी माना कि महिला की आय क्षमता पिता को उसकी अभिभावकीय जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करती।

## भारत में बाल अभिरक्षा

- भारत में बाल अभिरक्षा व्यक्तिगत कानूनों, अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, एवं न्यायालयों द्वारा विकसित न्यायिक सिद्धांतों के मिश्रण से शासित होती है।
- भारतीय बाल अभिरक्षा कानून का एकीकृत सिद्धांत यह है कि बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित सभी अन्य विचारों से ऊपर है, जिसमें अभिभावकीय अधिकार, वैधानिक प्राथमिकताएँ एवं पारंपरिक पदानुक्रम शामिल हैं।
- बाल अभिरक्षा के प्रकार:
  - एकल अभिरक्षा (Sole Custody):** बच्चा एक अभिभावक के साथ रहता है और दूसरे अभिभावक को मुलाकात का अधिकार मिल सकता है।
  - संयुक्त अभिरक्षा (Joint Custody):** बच्चा अभिभावकों के बीच अदल-बदल करता है, इसे संतुलित पालन-पोषण सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों द्वारा तीव्रता से प्राथमिकता दी जा रही है।
  - तृतीय-पक्ष अभिरक्षा (Third-Party Custody):** यदि दोनों अभिभावक अयोग्य हों तो दादा-दादी या रिश्तेदारों को दी जाती है।
- अभिभावकत्व तब समाप्त हो जाता है जब बच्चा वयस्कता (अठारह वर्ष) प्राप्त कर लेता है, जब अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, उसे हटा दिया जाता है, या वह इस्तीफा दे देता है, या महिला वार्ड के मामले में, उसके विवाह पर।

स्रोत: TH

## हिमाचल प्रदेश विनियमित भांग की खेती की राह पर

### संदर्भ

- हिमाचल प्रदेश औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध और विनियमित करने के लिए नीति को अंतिम रूप दे रहा है।

### भांग के बारे में

- भांग की खेती में कैनबिस सैटिवा पौधे को इसके रेशों (भांग) या मनो-सक्रिय यौगिकों (गांजा) के लिए उगाना शामिल है।

- **कानूनी और नियामक ढाँचा:** भांग की खेती मादक द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS), 1985 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
  - ▲ हालाँकि, यह अधिनियम राज्यों को औषधीय, औद्योगिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए सख्त विनियमन के अंतर्गत भांग की खेती की अनुमति देता है।
- भांग-आधारित चिकित्सा उपचार में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल (THC) और कैनाबिडियोल (CBD) जैसे यौगिकों का उपयोग किया जाता है, जो पुराना दर्द, मतली, मांसपेशियों में ऐंथन और मिर्गी जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में सहायता करते हैं, और शरीर की एंडोकैनाबिनॉइड प्रणाली के साथ संपर्क करते हैं।

**स्रोत:** TH

## हनिमाद्हू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

### संदर्भ

- केंद्र ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से मालदीव के अनुरोध का अध्ययन करने को कहा है, जिसमें भारतीय कंपनियों से उसके हाल ही में उन्नत हनिमाद्हू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन करने में सहायता मांगी गई है।

### हनिमाद्हू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (HAQ) के बारे में

- हनिमाद्हू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव के उत्तरी भाग में हा धालु एटोल के हनिमाद्हू द्वीप पर स्थित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
- यह उत्तरी एटोल्स के लिए प्राथमिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो राजधानी माले से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में है।
- हनिमाद्हू हवाई अड्डे को प्रारंभ में 1986 में एक घेरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया था और बाद में 2012 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया।
- भारत ने EXIM बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी \$800 मिलियन की ऋण रेखा के साथ हनिमाद्हू हवाई अड्डे के पुनर्विकास और विस्तार कार्यों का समर्थन किया।

- ▲ उन्नयन कार्यों में 2,465-मीटर का रनवे शामिल है, जो एयरबस A320 विमान को उतारने में सक्षम है, और एक नया यात्री भवन जो प्रति वर्ष 1.3 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है।

**स्रोत:** TH

## महाराष्ट्र में प्रमुख छह-लेन ग्रीन कॉरिडॉर को स्वीकृति

### संदर्भ

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने महाराष्ट्र में नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट को जोड़ने वाले छह-लेन, एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर के निर्माण को स्वीकृति दी है।

### परिचय

- 374 किलोमीटर लंबी परियोजना को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) टोल मोड पर विकसित किया जाएगा।
  - ▲ BOT मॉडल एक परियोजना ढाँचा है जिसमें एक निजी कंपनी एक बड़ी परियोजना का निर्माण, वित्तपोषण और संचालन करती है, एक निर्धारित अवधि के लिए लागत वसूलती/लाभ कमाती है, तथा फिर स्वामित्व सरकार को वापस हस्तांतरित कर देती है।
- यह क्षेत्रीय और अंतर-राज्यीय संपर्क में सुधार करेगा, साथ ही पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारत की एकीकृत परिवहन अवसंरचना को मजबूत करेगा।

### पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP)

- इसे 2021 में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बहु-मोडल संपर्क अवसंरचना प्रदान करने और भारत भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए लॉन्च किया गया था।
- यह किसी एक मंत्रालय के अधीन नहीं है बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा समन्वित है।
- यह योजना लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से आवाजाही के लिए निर्बाध एवं कुशल संपर्क प्रदान करेगी, जिससे अंतिम-मील संपर्क में सुधार होगा और यात्रा समय कम होगा।

- पीएम गतिशक्ति सात इंजनों द्वारा संचालित है: रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।
- 57 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग जिनमें 8 अवसंरचना, 22 सामाजिक और 27 आर्थिक एवं अन्य मंत्रालय/विभाग शामिल हैं, PMGS NMP पर शामिल किए गए हैं।

स्रोत: TH

## DRDO द्वारा दो प्रलय मिसाइलों का साल्वो लॉन्च

### संदर्भ

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट से दो 'प्रलय' मिसाइलों का साल्वो प्रक्षेपण त्वरित क्रम में सफलतापूर्वक किया।

### परिचय

- प्रलय एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली अल्प-दूरी की अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है।
- रेंज और पेलोड:** प्रलय की परिचालन सीमा लगभग 400 किलोमीटर है और यह 500 से 1,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है।
- प्रणोदन:** इसे ठोस-ईंधन रॉकेट मोटर द्वारा संचालित किया जाता है।
- मिसाइल अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली** और एकीकृत एवियोनिक्स से लैस है, जो कठिन भूभागों में भी सटीक लक्ष्य भेदन सुनिश्चित करती है।
  - यह विभिन्न प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है ताकि व्यापक लक्ष्यों को भेदा जा सके।

स्रोत: PIB

## राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन रूपरेखा (NTRAF)

### समाचारों में

- हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन रूपरेखा (NTRAF) लॉन्च की।

### NTRAF

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन रूपरेखा (NTRAF) एक मानकीकृत, वस्तुनिष्ठ ढाँचा है जो प्रयोगशाला अनुसंधान से लेकर पूर्ण वाणिज्यिक तैनाती तक प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता का आकलन करता है, जिसमें 9 प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRLs) शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास (R&D) फंड्स के लिए परिचालन रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करना है।

### रूपरेखा की प्रमुख विशेषताएँ

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:** वैश्विक मानकों (जैसे NASA) से अनुकूलित, लेकिन भारतीय R&D पारिस्थितिकी तंत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप।
- वस्तुनिष्ठता बनाम व्यक्तिनिष्ठता:** प्रत्येक विकास चरण के लिए संरचित, साक्ष्य-आधारित चेकलिस्ट के साथ गुणात्मक अनुमान को प्रतिस्थापित करता है।
- क्षेत्र-विशिष्ट सूक्ष्मताएँ:** स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष परिशिष्ट शामिल करता है, यह मान्यता देते हुए कि विकास मार्ग अलग-अलग होते हैं।
- स्व-मूल्यांकन उपकरण:** परियोजना अन्वेषकों को यथार्थवादी रूप से अपनी स्थिति का आकलन करने और फंडिंग से पहले तकनीकी अंतराल की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: PIB

## अमेजन के डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार

### समाचारों में

- डंक रहित मधुमक्खियाँ विश्व में प्रथम कीट बन गई हैं जिन्हें उनके पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं।

### डंक रहित मधुमक्खियाँ

- ये अमेजन वर्षावन के पेरूवियन हिस्से में पाई जाती हैं, जिनमें यूरोपीय मधुमक्खियों की तरह डंक नहीं होता।

- पारिस्थितिक भूमिका:** ये वर्षावन की प्रमुख परागणकर्ता हैं, जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं।
  - ये ग्रह की सबसे पुरानी मधुमक्खी प्रजाति हैं और अमेजन की 80% से अधिक वनस्पतियों का परागण करती हैं, जिनमें कॉफी, चॉकलेट, एवोकाडो एवं ब्लूबेरी जैसी वैश्विक स्तर पर प्रिय फसलें शामिल हैं।
- खतरे:** ये जलवायु परिवर्तन, बनों की कटाई और कीटनाशकों के साथ-साथ यूरोपीय मधुमक्खियों से प्रतिस्पर्धा जैसी घातक चुनौतियों का सामना करती हैं।
- प्रदान किए गए अधिकार:** नेटिव स्टिंगलेस बीज के अधिकारों की घोषणा उनके अस्तित्व, फलने-फूलने, स्वस्थ जनसंख्या बनाए रखने, प्रदूषण-मुक्त आवास में रहने, प्राकृतिक चक्रों को पुनर्जीवित करने और यदि उन्हें हानि पहुँचाई जाए तो कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार को मान्यता देती है।

**स्रोत:** DTE

## कीटों में माइटोकॉन्ड्रिया का विकास

### समाचारों में

- गुएलफ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजा है कि कीट नर और मादा कैसे उत्पन्न करते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के विकास की दर को प्रभावित करता है।

### माइटोकॉन्ड्रिया क्या है?

- माइटोकॉन्ड्रिया डिल्ली-बद्ध कोशिकांग हैं जो कोशिका की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
- माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) नामक छोटे अणु में संग्रहीत होती है।
- माइटोकॉन्ड्रिया में अपने छोटे गुणसूत्र होते हैं।
- माइटोकॉन्ड्रिया प्राचीन जीवाणु से उत्पन्न हुए और एक छोटा जीनोम बनाए रखते हैं।

- अधिकांश माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन अब नाभिकीय डीएनए द्वारा एन्कोड किए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मातृसत्तात्मक रूप से (केवल महिलाओं से) विरासत में मिलता है।

### हालिया अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- हैप्लो-डिप्लॉइड (HD) प्रजातियों जैसे चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और ततैया में नर हैप्लॉइड होते हैं और मादा डिप्लॉइड होती हैं, जबकि डिप्लो-डिप्लॉइड (DD) प्रजातियों में दोनों लिंग डिप्लॉइड होते हैं।
- हालिया अध्ययन ने 783 परिवारों में 86,000 प्रजातियों का सर्वेक्षण किया और पाया कि HD प्रजातियाँ माइटोकॉन्ड्रियल COI जीन (साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज सबयूनिट I) में लगभग 1.7 गुना अधिक परिवर्तन दिखाती हैं, जिनमें अधिक इंसर्शन एवं डिलीशन शामिल हैं, DD प्रजातियों की तुलना में।
- यह तीव्र विकास माना जाता है कि HD नर केवल प्रत्येक नाभिकीय जीन की एक प्रति ले जाते हैं, जिससे उत्परिवर्तन तुरंत चयन के लिए उजागर हो जाते हैं और परस्पर क्रिया करने वाले माइटोकॉन्ड्रियल जीनों को अधिक तीव्रता से अनुकूलित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

### प्रभाव

- ये निष्कर्ष प्रजनन जीवविज्ञान और माइटोकॉन्ड्रियल विकास के बीच एक संबंध को उजागर करते हैं, जिनका कीट जैव विविधता को ट्रैक करने के लिए प्रभाव है, क्योंकि COI बारकोड विभिन्न प्रजातियों में अलग-अलग दरों पर विकसित हो सकते हैं।

**स्रोत:** TH

## राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA)

### संदर्भ

- 2025 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 92% से अधिक दोषसिद्धि दर प्राप्त की, 26/11 आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया, और पूरे देश में आतंकवाद तथा संगठित अपराध पर अपनी कार्रवाई को तीव्र किया।

## राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)

- स्थापना:** NIA अधिनियम, 2008 के अंतर्गत, 26/11 मुंबई हमलों के बाद।
- कार्य:** केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी।
- अधिदेश:** भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संधियों आदि को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच।
- NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019:**
  - अधिकार क्षेत्र का विस्तार:** भारत के बाहर भारतीय नागरिकों/हितों से जुड़े अनुसूचित अपराधों की जांच कर सकती है।
  - विस्तारित मंडेट:** विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908; मानव तस्करी; साइबर आतंकवाद; शास्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अपराधों को शामिल करता है।
- मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- विशेष न्यायालय:** कुल NIA विशेष न्यायालय: 51
- विशेष NIA न्यायालय:** 2 (रांची और जम्मू)।

स्रोत: TH

## ग्राम रक्षा गार्ड (VDG)

### संदर्भ

- जम्मू क्षेत्र की चिनाब घाटी पर आतंकवादियों के बढ़ते फोकस के बीच, सेना ने उन स्थानीय नागरिकों को चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जिन्होंने ग्राम रक्षा गार्ड (VDG) के रूप में कार्य करने की पेशकश की।

### परिचय

- उद्देश्य:** उनकी परिचालन तत्परता और सुरक्षा बलों के साथ समन्वय को बढ़ाना।
- प्रशिक्षण:** VDG को आत्मरक्षा और बंकरों में स्थिति लेने का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें पर्वतीय युद्ध का भी प्रशिक्षण दिया गया।
- VDG को उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसमें हथियार संचालन, फायरिंग अभ्यास और बुनियादी युद्ध ड्रिल पर ध्यान केंद्रित किया गया।**
- महत्व:** प्रशिक्षण पहले सशस्त्र बलों और स्थानीय रक्षा समूहों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे बुनियादी स्तर पर समग्र सुरक्षा और लचीलापन में योगदान मिलता है।

स्रोत: TH

